समक्ष प्रेम चंद जैन और जेएम टंडन, जेजे

हरविंदर कौर आदि, - ***याचिकाकर्ता,***

बनाम

गोधा राम, आदि, - ***उत्तरदाता।***

***सिविल संशोधन सं.* 1977 का 1198**

24 अगस्त, 1978

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का वी) - *धारा* 115 *और आदेश* 26, नियम 9 - *स्थानीय आयुक्त को नियुक्त करने से इनकार करने वाला आदेश - क्या संशोधन योग्य है।*

निर्धारित किया गया, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 में दो भाग हैं, पहला उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनमें उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किया गया एक मामला है जिसमें उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं है; दूसरा उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय की शक्ति "किसी भी मामले के संबंध में प्रयोग योग्य है जो तय किया गया है"। धारा 115 में स्पष्टीकरण जोड़ने का इरादा केवल "मामले का निर्णय" शब्दों को परिभाषित करना था, अर्थात, एक संशोधन वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान पारित आदेश के खिलाफ होगा। लेकिन स्पष्टीकरण को यह अर्थ नहीं दिया जा सकता है कि मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान किए गए प्रत्येक आदेश को संशोधित किया जाएगा। स्पष्टीकरण को जो अर्थ दिया जा सकता है वह यह है कि मुकदमे या कार्यवाही के दौरान किया गया आदेश केवल तभी संशोधित किया जाएगा जब यह विवाद में पार्टियों के कुछ अधिकार या दायित्व को निर्धारित या निर्णय लेता है। इस प्रकार एक संशोधन एक मध्यस्थ आदेश के खिलाफ होगा यदि यह विवाद में पार्टियों के कुछ अधिकार या दायित्व को निर्धारित या निर्णय लेता है। हालांकि, उपरोक्त परीक्षण की संतुष्टि के बाद भी, संशोधन की शक्ति उच्च न्यायालय द्वारा उपधारा (1) और संहिता की धारा 115 के परंतुक के तहत लगाई गई सीमाओं के अधीन प्रयोग की जाएगी। स्थानीय आयुक्त को नियुक्त करने से इनकार करने वाला आदेश किसी भी मुद्दे पर फैसला नहीं करता है और न ही यह मुकदमे के प्रयोजनों के लिए पार्टियों के किसी अधिकार या दायित्व पर निर्णय लेता है और इसलिए, संशोधन योग्य नहीं है।
(पैरा 4, 5, 7 and 8).

गोवर्धन दास गोपी नाथ बनाम *श्रीमती अमोलोक राज.,* 1975 कर। एल.टी. 744 को **खारिज कर दिया गया**।

सीपीसी की धारा *115* के तहत *श्री सुभाष चन् द्र, एच.सी.एस. उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, कैथल; दिनांक 8 अगस्त* 1977, *स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति के आवेदन को खारिज करते हुए।*

याचिकाकर्ताओं की ओर *से एच.एल. सरीन, अधिवक्ता।*

सी. बी. गोयल, अधिवक्ता, *प्रतिवादियों के लिए।*

निर्णय

प्रेम चंद जैन, जे.

1. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 3 मई, 1978 के अपने आदेश के *माध्यम से* दिए गए संदर्भ के आधार पर, कानून का प्रश्न जिसके निर्धारण की आवश्यकता है, इस प्रकार तैयार किया जा सकता है: -

> "क्या संशोधन नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 26, नियम 9 के तहत पारित आदेश के खिलाफ है जो स्थानीय आयुक्त को नियुक्त करने से इनकार करता है?"

यह संदर्भ इसलिए दिया गया है क्योंकि विद्वान न्यायाधीश की राय में मामले के इस पहलू पर विचारों का टकराव प्रतीत होता है। *दलमीर सिंह उर्फ दलमीरा* बनाम *संत प्रकाश और अन्य*[1], आरएस नरूला, सीजे- (जैसा कि वह तब थे), पट्टर, जे. के फैसले के आधार पर, *मेसर्स मोहिंदर कुमार राजिंदर प्रकाश* बनाम *बशशर नाथ*[2] ने कहा कि इस तरह के आदेश के खिलाफ कोई संशोधन नहीं है। इसके विपरीत, एस. सी. मित्तल, जे. ने *मैसर्स गोवर्धन दास गोपी नाथ* बनाम श्रीमती *अमोलक राज* (3) के मामले में कहा है कि ऐसा करने से इनकार करने वाला एक आदेश जारी किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत आयोग जारी करना पुनरीक्षण योग्य है-

2. याचिकाकर्ताओं के वकील श्री सरीन ने तर्क दिया कि एक पुनरीक्षण एक स्थानीय आयुक्त को नियुक्त करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ है और *मेसर्स गोवर्धन दास गोपी नाथ के* मामले में लिया गया दृष्टिकोण सही दृष्टिकोण था और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। *मेसर्स गोवर्धन दास गोपी नाथ बनाम श्रीमती अमोलक राज*[3] *के* मामले में दिए गए तर्क पर भरोसा करने के अलावा, विद्वान वकील ने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में जोड़े गए स्पष्टीकरण पर भरोसा किया, जो निम्नलिखित शब्दों में है: –

> "इस धारा में, 'किसी भी मामले पर फैसला किया गया है' शब्द में मुकदमा या अन्य कार्यवाही के दौरान किया गया कोई भी आदेश, या किसी मुद्दे पर फैसला करने वाला कोई भी आदेश शामिल है।"

उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर, श्री सरीन के साथ यह तर्क दिया गया था कि आयोग नियुक्त करने से इनकार करने वाला आदेश एक मुकदमे के दौरान पारित किया गया था और ऐसा आदेश 'मामले के फैसले' की अभिव्यक्ति के भीतर आता है।

3. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम विद्वान वकील की दलील से सहमत होने में असमर्थ हैं।

4. धारा 115 में दो भाग होते हैं, पहला उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनमें उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किया गया एक मामला है

[1] 1975 के सीआर 1459 पर 21 सितंबर, 1976 को फैसला लिया गया
[2] 1976 पी.एल.आर. 280
[3] 1975 करी एल.जे. 744

जिसमें उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं है; दूसरा, उन परिस्थितियों को निर्धारित करता है जिनमें अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय की शक्ति "किसी भी मामले के संबंध में प्रयोग योग्य है जो तय किया गया है"। "मामले का निर्णय" शब्द को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इस सवाल पर न्यायिक निर्णयों का टकराव था कि क्या "मामले का निर्णय" अभिव्यक्ति में मध्यस्थ आदेश शामिल थे या नहीं। हालांकि इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने मेजर एसएस खन्ना बनाम *ब्रिगेडियर एफ. जे. ढिल्लों*[4] में सुलझा लिया था।, फिर भी एक वार्ताकारी आदेश के खिलाफ संशोधन की विचारणीयता के बारे में सभी संदेहों को दूर करने के लिए, स्पष्टीकरण को वर्ष 1976 में संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। हालांकि, इस मामले में, स्पष्टीकरण अपने आप में कोई मदद नहीं करता है क्योंकि यह अभी भी तय किया जाना है कि स्पष्टीकरण के प्रावधानों को देखते हुए आयोग नियुक्त करने से इनकार करने वाला आदेश संशोधित होगा या नहीं? हमारे विचार में, इस मामले की परिस्थितियों में, उत्तर नकारात्मक में होना चाहिए।

5. वर्ष 1976 में धारा 115 के संशोधन से पहले, संशोधन की शक्ति उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) में लगाए गए प्रतिबंध के अधीन प्रयोग योग्य थी। जैसा कि पहले देखा गया था, "मामले का फैसला" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था और इस कारण से, इन शब्दों की व्याख्या के संबंध में न्यायिक निर्णयों का टकराव सामने आया था। स्पष्टीकरण जोड़ने का इरादा केवल "मामले का फैसला" शब्दों को परिभाषित करना था, यानी, एक संशोधन मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान पारित आदेश के खिलाफ होगा। लेकिन स्पष्टीकरण को यह अर्थ नहीं दिया जा सकता है कि मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान किया गया प्रत्येक आदेश संशोधित होगा। यहां तक कि बहस के दौरान विद्वान वकील श्री सरीन ने इस हद तक नहीं कहा कि वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान पारित प्रत्येक आदेश संहिता की धारा 115 के तहत संशोधित किया जाएगा।

6. इस स्थिति में, अब यह पता लगाना होगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा किस प्रकार के मध्यस्थ आदेशों को संशोधित किया जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर *बलदेवदास शिवलाल और अन्य* बनाम *फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, और अन्य*[5] मामले में उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप के निर्णय से उपलब्ध, जिसमें *मेजर एसएस खन्ना के मामले पर विचार करने के* बाद यह इस प्रकार देखा गया: –

> "लेकिन मेजर एस-एस खन्ना के मामले (1964) 4 एससीआर 409 = (एआईआर 1964 एससी 497) में यह तय नहीं किया गया था कि मुकदमे के दौरान अदालत का हर आदेश एक मामले के फैसले के बराबर है। एक मामले को तय कहा जा सकता है, अगर अदालत वाद के प्रयोजनों के लिए विवाद में पार्टियों के कुछ अधिकार या दायित्व का फैसला करती है; मुकदमे में प्रत्येक आदेश को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अर्थ के भीतर तय किए गए मामले के रूप में नहीं माना जा सकता है।

7. इस विषय पर और अधिक टाल-मटोल किए बिना पूर्वोक्त टिप्पणी के आलोक में, स्पष्टीकरण

[4] ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 497
[5] ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 406

को जो अर्थ दिया जा सकता है, वह यह है कि मुकदमे या कार्यवाही के दौरान किया गया आदेश केवल तभी संशोधित किया जाएगा जब यह विवाद में पार्टियों के कुछ अधिकार या दायित्व को निर्धारित या निर्णय देता है। इस प्रकार, एक संशोधन केवल एक मध्यस्थ आदेश के खिलाफ होगा यदि यह विवाद में पार्टियों के कुछ अधिकार या दायित्व को निर्धारित या निर्णय लेता है। हालांकि, उपर्युक्त परीक्षण की संतुष्टि के बाद भी संशोधन की शक्ति इस न्यायालय द्वारा उप-धारा (1) और नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के परंतुक के तहत लगाई गई सीमाओं के अधीन प्रयोग की जाएगी।

8. वर्तमान मामले के तथ्यों का विश्लेषण करते हुए, हम पाते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने केवल इस आधार पर आयोग जारी करने के आवेदन को खारिज कर दिया है कि संबंधित रिकॉर्ड पेश करके मुद्दा संख्या 3 साबित किया जा सकता है और सीमांकन आवश्यक नहीं था। इन टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने किसी भी मुद्दे पर फैसला नहीं किया और न ही उन्होंने मुकदमे के प्रयोजनों के लिए विवाद में पार्टियों के कुछ अधिकार या दायित्व पर निर्णय लिया।

9. मामले के कानून के अनुसार, संदर्भ मैसर्स *गोवर्धन दास गोपी नाथ का* मामला, को दिया जा सकता है एकमात्र निर्णय जिस पर श्री सरीन द्वारा भरोसा किया गया था और किस निर्णय के लिए बड़ी पीठ को संदर्भित करना आवश्यक था। हमारी पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अत्यंत सम्मान के साथ, उस निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। विद्वान न्यायाधीश ने *मेजर एस एस खन्ना के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और* मेसर्स साधु राम बली राम और एक अन्य बनाम *मैसर्स घनश्याम दास मदन लाई और अन्य* [6] *मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय* के आधार पर निर्णय दिया । इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बॉम्बे में रहने वाले दो गवाहों से पूछताछ के लिए प्रतिवादी के आवेदन को खारिज करने का आदेश "तय किए गए मामले" की अभिव्यक्ति के भीतर आता है।

10. जैसा कि फैसले के पहले भाग में पहले ही देखा जा चुका है, *मेजर एसएस खन्ना के मामले को* बलदेवदास शिवलाल के मामले में *सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप द्वारा समझाया गया है,* और उसमें निर्धारित परीक्षण को ध्यान में रखते हुए, अदालत के आदेश के परिणामस्वरूप मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान विवाद में शामिल पक्षों के कुछ अधिकार या दायित्व का निर्णय होना चाहिए। मैसर्स में उल्लिखित प्रकार का कमीशन जारी करने से इनकार करने वाला आदेश। *गोवर्धन दास गोपी नाथ का* मामला उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता. आगे यह देखा जा सकता है कि मैसर्स मैसर्स के तथ्य *साधु राम बली राम का* मामला अलग था क्योंकि उस मामले में एक मुद्दे की जिम्मेदारी गलत तरीके से रखी गई थी और उस प्रश्न पर निर्णय लेते समय यह माना गया था कि ऐसा आदेश संशोधित किया जाएगा।

11. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि आदेश 26, नियम 9 के तहत पारित आदेश और मैसर्स मैसर्स में लिए गए दृष्टिकोण के खिलाफ कोई संशोधन नहीं होगा। *मोहिंदर कुमार राजिंदर प्रकाश; दलमीर सिंह उर्फ दलमीरा और मंगल सिंह और एक अन्य* बनाम *पियारा लाल* [7], मामले सही कानून निर्धारित करते हैं।

12. हालांकि, फैसले से अलग होने से पहले, यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यह एक सामान्य

[6] ए.आई.आर. 1975 पी.बी. और हरियाणा 174
[7] 1971 पी.एल.आर. 531

नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किसी भी मामले में आदेश 26 के किसी अन्य प्रावधान के तहत पारित एक मध्यस्थ आदेश के खिलाफ संशोधन नहीं होगा, और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर होगा कि यह पता लगाना होगा कि क्या मध्यस्थ आदेश, जिसके खिलाफ एक पुनरीक्षण दायर करने की मांग की गई है, मुकदमे के प्रयोजनों के लिए विवाद में पार्टियों के कुछ अधिकार या दायित्व का निर्णय लिया है या नहीं।

13. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, यह संशोधन याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के रूप में कोई आदेश नहीं देते हैं। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 7 नवंबर, 1978 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी